अनावश्यक आक्रामकता

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

01 जनवरी, 2022

भारत, चीन को सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए पिछले समझौतों का पालन करना चाहिए।

30 दिसंबर को चीनी सरकार ने घोषणा की है कि वह अरुणाचल प्रदेश में 15 स्थानों के नाम अपने अनुसार रखेगी, इस कदम ने पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और तनावग्रस्त कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य स्पष्ट रूप से "मानकीकरण" करना है कि कैसे भारतीय राज्य के स्थानों को आधिकारिक चीनी मानचित्रों में दर्शाया गया है, जो पूरे अरुणाचल को "दक्षिण तिब्बत" के रूप में दिखाते हैं।

भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस कदम के जवाब में एक बयान में कहा कि अपने आप अविष्कार कर लिए गए नामों के ले आने से जमीन पर किसी भी तथ्य और भारत के अभिन्न अंग के रूप में अरुणाचल की स्थिति को "बदल" नहीं देगा। जैसा कि विदेश मंत्रालय ने उल्लेख किया है, यह पहली बार नहीं है जब बीजिंग ने ऐसा किया है।

2017 में, चीनी अधिकारियों ने अरुणाचल में छह स्थानों के लिए "आधिकारिक" नाम जारी किए। पहला उदाहरण दलाई लामा के राज्य के दौरे के बाद आया, जिसका बीजिंग ने विरोध किया था। इस अवसर पर सूची लंबी है, और इसमें न केवल आठ शहर शामिल हैं बल्कि चार पहाड़, दो नदियां और एक पहाड़ी दर्रा भी शामिल है। इस सूची में अरुणाचल के 25 में से 11 जिले शामिल हैं, जो पश्चिम में तवांग से लेकर उत्तर में दिबांग घाटी और पूर्व में अंजॉ तक फैले हुए हैं। स्थानों के विस्तार से पता चलता है कि पूरे राज्य में चीनी दावों को दोहराने के लिए स्थानों को चुना गया था।

यदि नवीनतम कदम काफी हद तक प्रतीकात्मक ही हो और भले ही इससे व्यवहारिक धरातल पर कुछ नही बदलेगा, फिर भी इसे वर्तमान सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में चीन के सीमा परिवर्तन के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए।

नामकरण की घोषणा 1 जनवरी, 2022 को लागू होने वाले एक नए सीमा कानून से पहले की गई थी। कानून, जिसे मार्च 2021 में प्रस्तावित किया गया था और विभिन्न चीनी सरकारी निकायों को चीनी क्षेत्र की "रक्षा" करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया था।इस कानून को वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर वर्ष 2020 में गर्मियों से चीनी सेना द्वारा किए गए उल्लंघनों को औपचारिक रूप देने के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका दिल्ली ने विरोध भी किया है।

एलएसी को फिर से तैयार करने के लिए चीन के एकतरफा उपायों पर मुहर लगाई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने नवीनतम कदम का बचाव करते हुए कहा कि मामला "चीन की संप्रभुता के भीतर" था। फिर भी, 2019 में जम्मू और कश्मीर के भारत के

अपने आंतरिक पुनर्गठन पर बीजिंग का एक बहुत अलग दृष्टिकोण था, जिस पर न केवल चीन ने तीखे बयान जारी किए, बल्कि बीजिंग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मामले को उठाया। इस सप्ताह घोषणा तब हुई जब भारत और चीन एलएसी के साथ रुकी हुई विघटन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राजनयिक और सैन्य दोनों स्तरों पर लगे हुए हैं।

संबंधों को बहाल करने के साथ-साथ सीमाओं के साथ यथास्थिति के लिए आपसी संवेदनशीलता और पिछले समझौतों के पालन की आवश्यकता होगी, जो कि पहले से ही मतभेदों की लंबी सूची का विस्तार करने वाले अनावश्यक उकसावे के बजाय शांति बनाए रखने में मदद करते हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. हाल ही में चीन ने भारत के किस राज्य को दक्षिणी तिब्बत के रूप में दर्शाया है?

(क) लद्दाख

(ख) अरुणाचल प्रदेश

(ग) असम

(घ) उत्तराखण्ड

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Which state of India has been shown by China as Southern Tibet recently?

(a) Ladakh

(b) Arunachal Pradesh

(c) Assam

(d) Uttarakhand

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. चीन के द्वारा हाल ही में अरुणाचल में गांवों के नाम परिवर्तित करने से भारत-चीन सीमा विवाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चीन के इस कदम के उठाने के क्या प्रतीकात्मक निहितार्थ हो सकते हैं? (250 शब्द)

Q. How will China's recent renaming of villages in Arunachal affect the India-China border dispute? What could be the symbolic implications of China's move? (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।